

03 अरविंद केजरीवाल को ED ने भेजा छठा समन...

06 किसानों की मांगों पर सहानुभूति से विचार हो

08 रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव बिजेड़ी की समर्थन से राज्यसभा जायेंगे...

दिल्ली में किन रास्तों से एंट्री, कौन से बॉर्डर पूरी तरह सील; किसान आंदोलन पर जाने ट्रैफिक रूट

किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए दिल्ली की कई सीमाएं बंद कर दी गई हैं। रास्ते पर बड़े-बड़े सीमेंट के ब्लॉक खड़े कर दिए गए हैं। इसके अलावा बैरिकेडिंग के ऊपर कटीले तार लगाए गए हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि दिल्ली जाने के लिए कौन-कौन से रास्ते खुले हैं और कौन-कौन से रास्ते बंद हैं।



संजय बाटला

नई दिल्ली। किसानों के दिल्ली कूच के एलान के बाद राष्ट्रीय राजधानी की सभी सीमाओं पर पुलिस का कड़ा पहरा कर दिया गया है। किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए बॉर्डर पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस की ओर से रास्ते पर बड़े-बड़े सीमेंट के ब्लॉक खड़े कर दिए गए हैं। इसके अलावा बैरिकेडिंग के ऊपर कटीले तार लगाए गए हैं।

जाम से जनता बेहाल
बैरिकेडिंग और जांच के कारण मंगलवार को दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर पर 10 किमी लंबा जाम देखने को मिला था। इससे लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए दिल्ली की कई सीमाएं बंद कर दी गई हैं। ऐसे में यह बात जानना जरूरी है कि दिल्ली जाने के लिए कौन-कौन से रास्ते खुले हैं और कौन-कौन से रास्ते बंद हैं।

दिल्ली के ये बॉर्डर सील
किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली का सिंधु बॉर्डर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कल तक पैदल यात्री बॉर्डर पर आ जा रहे थे। हालांकि, बुधवार को सिंधु बॉर्डर पर पूरी तरह से पैदल यात्रियों के लिए भी रास्ता बंद कर

दिया गया है। पैदल यात्री जैसी बैरियर फलंग कर दिल्ली की सीमा में दाखिल हो रहे हैं। जहां-जहां पैदल जाने के लिए रास्ता था, उसे डंपर लगाकर बंद कर दिया गया।

इसके अलावा दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर भी आवागमन पूरी तरह से बंद है। पुलिस का टीकरी बॉर्डर पर कड़ा पहरा है, यहां पर बहु स्तरीय बैरिकेडिंग लगाई गई है। खास बात है कि इस बार इंतजामों में हरियाणा व दिल्ली पुलिस के बीच पहले के मुकाबले तालमेल अधिक देखने को मिल रहा है। यहां दिल्ली पुलिस के साथ सीमा सुरक्षा बल कर्मियों की भी तैनाती की गई है।

दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी
उत्तर प्रदेश की ओर से दिल्ली जाने के लिए रास्ते खुले हैं। गाजियाबाद और नोएडा की तरफ से जाने वालों रास्तों पर ट्रैफिक सामान्य है। हालांकि, बॉर्डर पर चेकिंग के कारण कुछ रास्ते जरूर प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करके कहा कि डीएनडी फ्लाईवे पर चेकिंग कारण, डीएनडी फ्लाईवे के दोनों कैरिज्वे पर भारी ट्रैफिक है। नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से नोएडा जाने वाले यात्रियों को चिल्ला बॉर्डर मार्ग के रास्ते जाने की सलाह दी गई है।

दिल्ली मेट्रो में अब तक के सफर का टूटा रिकॉर्ड, एक दिन में लोगों ने की 71 लाख से ज्यादा यात्राएं



किसान आंदोलन के चलते दिल्ली मेट्रो में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। मंगलवार को दिल्ली मेट्रो में 71 लाख नौ हजार से अधिक यात्राएं लोगों (पैसेंजर जर्नी) ने की जो अब तक का सर्वाधिक है। यलो लाइन ब्लू लाइन रेड लाइन सहित दिल्ली मेट्रो के अन्य सभी कॉरिडोर और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की मेट्रो में भी यात्रियों की संख्या बढ़ी है।

नई दिल्ली। किसानों के दिल्ली कूच से सड़क मार्ग से वाहनों की आवाजाही बुरी तरह से बाधित हुई है। इससे दिल्ली मेट्रो में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। इस कारण मेट्रो में यात्रियों की संख्या का रिकार्ड टूट गया। मंगलवार को दिल्ली मेट्रो में 71 लाख नौ हजार से अधिक यात्राएं लोगों (पैसेंजर जर्नी) ने की, जो अब तक का सर्वाधिक है। यलो लाइन, ब्लू लाइन, रेड लाइन सहित दिल्ली मेट्रो के अन्य सभी कॉरिडोर और

एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की मेट्रो में भी यात्रियों की संख्या बढ़ी है। प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए राजधानी की सभी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के साथ कई सड़कें बंद कर दी गई हैं। 110 फरवरी, 2020 को मेट्रो में 66 लाख 18 हजार 717 यात्राएं यात्रियों ने की थी, जबकि पिछले 28 अगस्त, 2023 को मेट्रो में 68 लाख 16 हजार 252 यात्राएं यात्रियों ने की थी। इसके अगले ही दिन 29 अगस्त को यह रिकार्ड भी टूट गया। 29 अगस्त को मेट्रो में 69 लाख 94 यात्राएं लोगों ने की थी।

13 फरवरी को टूटा यह रिकॉर्ड
चार सितंबर, 2023 को मेट्रो में 71 लाख तीन हजार 511 यात्राएं लोगों ने की थी। इसमें से 38 लाख नौ हजार 919 यात्राएं (53.63 प्रतिशत) यात्रियों ने येलो लाइन व ब्लू लाइन की मेट्रो में की थी। 13 फरवरी को यह रिकार्ड भी टूट गया।

वीवीआईपी द्वारा प्रयोग होने वाली सड़क ही अगर है खराब तो बाकी सड़कों का क्या होगा, बड़ा सवाल?

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। आईएमटी चंदावली, एफएमडीए ऑफिस एवं एचएसआईडीसी का ऑफिस के लिए जाने के लिए जिस सड़क से जाना पड़ता है उसके हालात बहुत ही ज्यादा चिंताजनक हैं और यही से रोजाना 3

आईएसएस ऑफिसर, चार एचसीएस ऑफिसर के साथ एफएमडीए के कई स्पेशलिस्ट चीफ इंजीनियर चीफ इंजीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर चीफ इंजीनियर मोबिलिटी एवं बड़े-बड़े अन्य अधिकारी रोजाना निकलते हैं। इन सभी के साथ आईएमटी के के कई प्रधान, कई अध्यक्ष

कई कंपनियों के मालिक और बड़े-बड़े अधिकारी निकलते हैं लेकिन शायद इन सभी ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं अरे कुछ भी बोलना नहीं चाहते। आपको यह जान कर और भी आश्चर्य होगा की यहीं से पुलिस के अधिकारी भी निकलते हैं क्योंकि उनके ऑफिस भी इसी रोड पर है।

अब आम जनता स्वयं यह समझे की जब इतनी वीआईपी सड़क को दुरुस्त करने के लिए विभाग की आंखें बंद हैं तो आम सड़कों का क्या होगा हाल वह भी जब वाहन खरीदने के समय वाहन मालिक से वन टाइम रोड टैक्स, पार्किंग टैक्स सरकार वसूल रही है और उसके

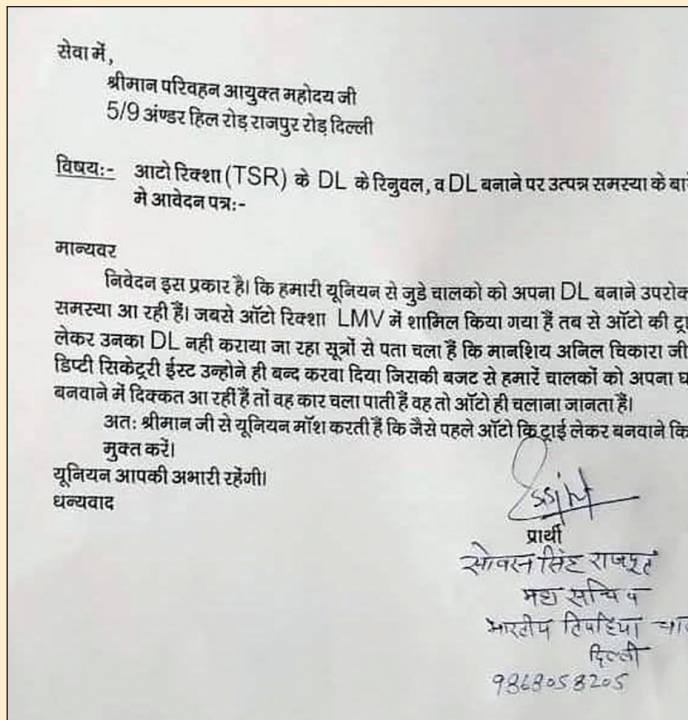
साथ ही सड़कों पर टोल टैक्स वसूल रही है जनता से देवेंद्र सिंह सदस्य स्टेट रोड सेपटी काउंसिल हरियाणा सरकार एवं सदस्य मंत्री ऑफ पार्लियामेंट रोड सेपटी कमेटी भारत सरकार एवं सदस्य टास्क फोर्स स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा सरकार

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। हमारी यूनियन से जुड़े चालकों को अपना डीएल बनवाने के लिए समस्या आ रही है। ऑटो रिकशा एलएमवी में शामिल हैं जिस कारण ऑटो द्वारा ट्राई लेकर उनका डीएल नहीं बनाने दिया जा रहा है सूत्रों से पता चला है कि

अनिल चिक्कारा डिप्टी सचिव ईस्ट दिल्ली द्वारा ऑटो द्वारा ट्राई बन्द करवा दी गई थी जिसके कारण हमारे चालकों को अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में दिक्कत आ रही है क्योंकि वह कार नहीं चला सकते हैं उन्हें तो सिर्फ ऑटो ही चलाना जानता है।

सोबरन सिंह आटो यूनियन द्वारा आटो चालकों के लिए ऑटो से ड्राइविंग स्किल टेस्ट की ट्राई की मांग



दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का हालात नियर पुलिस लाइन फरीदाबाद सड़क टूटी पड़ी है कोई रोड साइन नहीं है कहां जाना है किसने और कोई अधिकारी देखने वाला नहीं है नेशनल हाईवे



डीआरए नाम की जो कंपनी इस पर कार्य कर रही है वह सड़क सुरक्षा के किसी भी नियम का पालन नहीं कर रहा है यही हालत जेवर एक्सप्रेस हाईवे के हैं भारत सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर केवल दौरा ही कर रहे हैं एक्शन नहीं ले रहे हैं और नेशनल हाईवे के अध्यक्ष के भी यही हालात हैं इस कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। देवेंद्र सिंह सदस्य स्टेट रोड सेपटी काउंसिल हरियाणा सरकार एवं सदस्य मंत्री ऑफ पार्लियामेंट रोड सेपटी कमेटी भारत सरकार एवं सदस्य टास्क फोर्स स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा सरकार।

डिलीवरी के बाद जरूर करें ये 5 योगासन, पिघल जाएगी पेट की झूलती चर्बी, बॉडी को मिलेगी परफेक्ट शेप

प्रेम नेंसी के दौरान वजन बढ़ना और डिलीवरी के बाद बेली फैट निकलना सामान्य बात है। इस झूलती चर्बी से छुटकारा पाने के लिए अक्सर महिलाएं परेशान रहती हैं। इससे निजात पाने के लिए इन योगासन की मदद ले सकती हैं।



प्रेमनेंसी के दौरान वजन बढ़ना और डिलीवरी के बाद बेली फैट निकलना सामान्य बात है। इस झूलती चर्बी से छुटकारा पाने के लिए अक्सर महिलाएं परेशान रहती हैं। शोप में आने के लिए कई महिलाएं डाइटिंग और वर्कआउट जैसे तमाम काम करती हैं, लेकिन इससे थकान महसूस हो सकती है। डिलीवरी के बाद यदि वजन कम करना ही है तो पहले शरीर को रिकवर होने के लिए समय दें, फिर योग की मदद ले सकती हैं। ऐसा करने से लटका हुआ पेट कम होगा और कुछ ही दिन में शोप में आने लगेंगी। आइए संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल दिल्ली की गायनेकॉलॉजिस्ट डॉ. ज्योति यादव से जानते हैं इन योग के बारे में-

प्रेमनेंसी के दौरान वजन बढ़ना और डिलीवरी के बाद बेली फैट निकलना सामान्य बात है। इस झूलती चर्बी से छुटकारा पाने के लिए अक्सर महिलाएं परेशान रहती हैं। इससे निजात पाने के लिए इन योगासन की मदद ले सकती हैं।

भुजंगासन: डिलीवरी के बाद बेली फैट को घटाने के लिए भुजंगास का अभ्यास एक बेहतर ऑप्शन है। इसको करने के लिए योगा मैट पर पेट के बल लेट जाएं, फिर, अपनी कोहिनियों को कमर से सटाएं और हथेलियां ऊपर की ओर रखें। अब धीरे-धीरे सांस भरते हुए, अपनी छाती को ऊपर की ओर उठाएं, इसके बाद पेट को धीरे-धीरे ऊपर उठा लें। इस स्थिति में 30 सेकंड तक रहें। अब सांस छोड़ते हुए, सिर को धीरे-धीरे जमीन की ओर नीचे लाएं। ध्यान रहे कि, इस प्रक्रिया को आप 3 से 5 बार दोहराएं।

त्रिकोणासन: पेट की झूलती चर्बी से छुटकारा पाने के लिए त्रिकोणासन की भी मदद ली जा सकती है। इस आसन को करने के लिए योगा मैट पर सीधे खड़े हो जाएं, फिर दोनों

पैरों के बीच 3-4 फीट की दूरी बनाएं। अब अपने दोनों हाथों को जांघों के बगल में रखकर बाहों को कंधे तक फैलाएं, फिर धीरे-धीरे सांस लेते हुए, दाएं हाथ को सिर के ऊपर ले जाएं, ध्यान रहे कि, इस दौरान आपका हाथ कान को छूना चाहिए, अब सांस छोड़ते हुए, अपने शरीर को बाईं तरफ को झुकाएं, इस मुद्रा में कुछ देर बने रहें। इसके बाद प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं। इसे 4-5 बार दोहरा सकते हैं।

नौकासन: डिलीवरी के बाद नौकासन की मदद से आप पेट की चर्बी घटा सकती हैं। इस आसन को करने के लिए योगा मैट पर बैठ जाएं, अब टांगों को सामने की तरफ फैलाएं, इसके बाद अपने दोनों हाथों को हिप्स से थोड़ा पीछे जमीन पर रखें। अब दोनों पैरों को सीधा रखते हुए ऊपर की तरफ उठाएं। अब धीरे-धीरे सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हुए पैरों को जमीन से 45 डिग्री तक उठाएं, इसके बाद सांस लेते हुए नाव के आकार में लगभग 10 से 20 सेकंड तक रहें। फिर धीरे-धीरे सांस छोड़ते हुए सामान्य मुद्रा में आएँ, इसको आप 3 से 5 बार दोहराएं।

वीरभद्रासन: डिलीवरी के बाद बेली फैट को घटाने के लिए वीरभद्रासन भी योगासन है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले योगा मैट पर सीधे खड़े हो जाएं, अब अपने दोनों पैरों को फैलाएं, पैरों के बीच 2-3 फीट की दूरी रखें, फिर अपने सीधे पैर को आगे लेकर आएँ और उल्टे पर को पीछे की ओर स्ट्रेच करें। इस दौरान हाथों को 180 डिग्री पर फैला कर रखें। इस अवस्था में 30-60 सेकंड तक रुकें। फिर प्रारंभिक मुद्रा में आ जाएँ, इस प्रक्रिया को 3-5 बार दोहराएं।

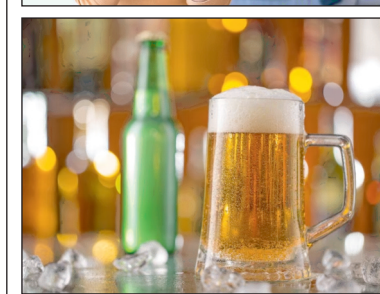
पश्चिमोत्तानासन: पेट की झूलती चर्बी से छुटकारा पाने के लिए पश्चिमोत्तानासन भी एक बेहतरी ऑप्शन है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले सुखासन में बैठ जाएं, अब अपने दोनों पैरों को सामने की ओर सीध में खोलकर बैठ जाएं, दोनों एड़ी और पंजे मिले रहेंगे। अब सांस छोड़ते हुए और आगे की ओर झुकते हुए दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगुठे पकड़ लें। माथे को घुटनों से लगाएं और दोनों कोहिनियां जमीन पर लगी रहेंगी, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस पोजिशन में आप खुद को 30 से 60 सेकंड तक रखें, धीमी सांसें लेते रहें। अब अपनी प्रारंभिक मुद्रा में लौट आएँ, इस प्रक्रिया को 3-5 बार दोहराएं।

लड़कियों की फर्टिलिटी खराब कर रही ये 5 गलत आदतें, तुरंत करें सुधार वरना बन सकती हैं संतान सुख में बाधा

देशभर में एक बड़ी संख्या में महिलाएं इनफर्टिलिटी की शिकार हो रही हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लड़कियों में इनफर्टिलिटी का कारण उनकी कुछ गलत आदतें होती हैं, जिस पर यह युवावस्था में ध्यान नहीं देती है। डॉक्टरों की मानें तो 18 से 30 साल की उम्र आपकी सेहत और फर्टिलिटी के लिहाज से बहुत सेंसिटिव होती है। इस उम्र में आपके द्वारा की गई छोटी से छोटी गलती भविष्य में कई गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती हैं। इन समस्याओं में हार्ट अटैक, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और इनफर्टिलिटी की समस्या सबसे अधिक है। ऐसे में जरूरी है कि आदतों को समय रहते हुए सुधारें, ताकि भविष्य कोई परेशानी न हो। आइए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज की गायनेकॉलॉजिस्ट डॉ. अमृता साहा से जानते हैं यंग लड़कियों की ऐसी 5 आदतों के बारे में, जो उनमें इनफर्टिलिटी की समस्या को बढ़ा रही हैं।

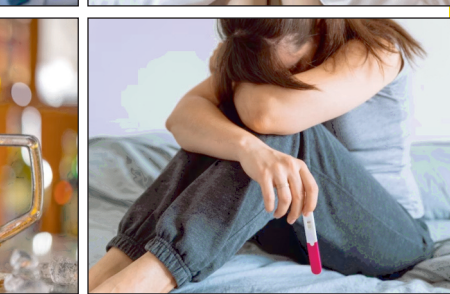
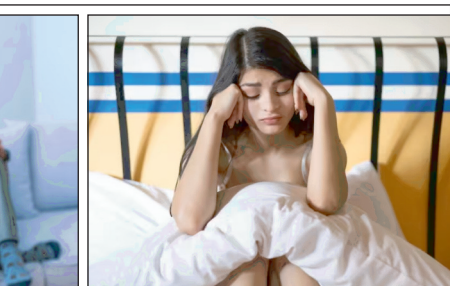
नींद की कमी: डॉ. अमृता साहा के मुताबिक, युवाओं में देर रात तक जागने की आदत उनकी सेहत को प्रभावित कर रही है। दरअसल, देर रात तक जागने से वे सुबह देर तक सोते हैं या आधी-अधूरी नींद लेकर ही काम पर लग जाते हैं। इस तरह कम नींद लेने वाले लोगों की फर्टिलिटी खराब होती रहती है। लड़कियों में नींद की कमी के चलते फर्टिलिटी की समस्या के साथ साथ पीरियड्स की अनियमितता, हॉर्मोनल असंतुलन और मोटापे का कारण बन सकती है। डॉक्टर शरीर को रोजाना 24 घंटे में से कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद लेने की सलाह देते हैं।

अनहेल्दी डाइट: युवाओं के खानपान में इन दिनों फास्ट फूड्स, जंक फूड्स, पैकेटबंद और प्रसिद्ध फूड्स का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। दरअसल फर्टिलिटी को सबसे ज्यादा प्रभावित खानपान की गलत आदतें ही करती हैं। अगर आप अपनी फर्टिलिटी को ठीक रखना चाहती हैं तो फास्ट फूड्स और जंक फूड्स को छोड़िए और अपनी डाइट में सब्जियों, फलों, अनाज और नैचुरल चीजों को शामिल करें, जिनसे आपको जरूरी



न्यूट्रिएंट्स मिल सके।

अल्कोहल: डॉक्टर की मानें तो शराब या अल्कोहल भी युवाओं में इन दिनों फैशन बन गया है। अल्कोहल यंग लड़कियों की फर्टिलिटी को बर्बाद कर रहा है। अल्कोहल का असर आपकी सेक्सुअल लाइफ, किडनी और लिवर पर बहुत बुरा पड़ता है।



अगर आप अल्कोहल की लत को एक बार में छोड़ नहीं सकती हैं, तो कम से कम इतना जरूर करें कि इसे सीमित मात्रा में लें।

स्मॉकिंग: यंग लड़के-लड़कियों में इन दिनों सिगरेट की लत एक आम बात हो गई है। सिगरेट पीने से आपके फेफड़ों और दिल की सेहत पर तो

फर्टिलिटी बिगाड़ रही ये गलत आदतें



असर पड़ता ही है, मगर इसके कारण लड़कियों के मां बनने की क्षमता भी कमजोर होती है। जो हां कम उम्र में सिगरेट पीने की लत के कारण महिलाओं के ओवरीज में बनने वाले अंडों के डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसके कारण उन्हें बार-बार मिसकैरेज का सामना भी करना पड़



सकता है।

अधिक एक्सरसाइज:

आजकल कुछ युवा तो बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं, जो फिटनेस के लिए पागल हुए जा रहे हैं और दिन के कई-कई घंटे जिम में वर्कआउट करते हुए बिता रहे हैं। रोजाना 1 से 2 घंटे की

एक्सरसाइज, जिसमें लाइट एक्सरसाइज और हाई इंटेन्सिटी एक्सरसाइज दोनों शामिल हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। मगर ओवरट्रेनिंग करने से आपके शरीर पर तो इसका बुरा असर पड़ता ही है, साथ ही आपकी फर्टिलिटी पर भी इसका बुरा असर पड़ता है।

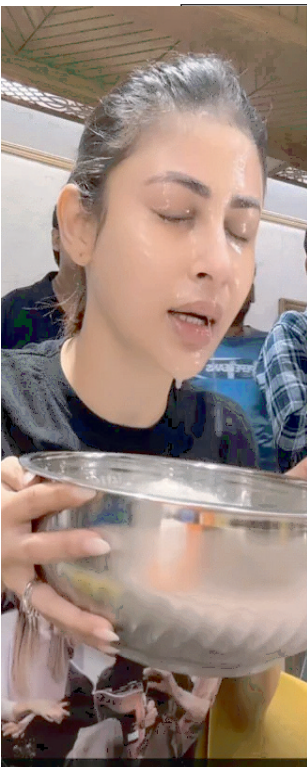
शीशे की तरह चमकने लगेगा चेहरा, ना ब्यूटीपार्लर का चक्कर ना महंगे क्रीम का, बस ये चीज फ्रीज से निकालें और...

ग्लोइंग स्किन के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस भी कई तरह के नुस्खों को अपने घर पर आजमाती हैं और अपने फेस को तरह-तरह के आईडिया देती रहती हैं। हाल ही में आलिया, कैटरिना द्वारा किए गए आइस हैक्स खूब वायरल हो रहे थे। इसे बेदाग त्वचा पाने वाला फ्रीज का नुस्खा भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसके लिए बस पानी की जरूरत होती है। अब पता चल रहा है कि इस हैक की मोनी रॉय भी बहुत बड़ी फैन हैं। मोनी रॉय ने आइस फेशियल करते हुए एक वीडियो शेयर किया है।

मोनी रॉय अपने स्किन केयर रूटीन में सुबह आइस फेशियल करती हैं। सुबह यह करने से फेस का पफनेस खत्म होता है। वीडियो में मोनी कुछ सेकंड के लिए बर्फ के पानी से भरे कटोरे में अपना चेहरा डुबाती हैं। ऐसा करने से यह फेस के अधिक तेल को कम करता है, मुँहासे से बचाता है और त्वचा की चमक को बढ़ाता है। आइस वॉटर फेशियल के बाद मोनी रॉय ने मॉइस्चराइजर के साथ इस रूटीन को फॉलो किया।

चेहरे पर बढ़ती झाड़ियाँ से हैं परेशान, कहीं हाइपरपिग्मेंटेशन तो नहीं? कारण जानकर करें ये 2 काम वरना स्किन हो जाएगी बदरंग

इसके बाद, वह अपने चेहरे की मालिश करने के लिए गॉल्ड-प्लेटेड टी-बार का उपयोग करती हुई देखी जा सकती हैं। यह फेस के टॉक्सिक पदार्थों को दूर करता है और आपकी त्वचा को टाइट करता है। एक बार स्टेप पूरा करने के बाद, मोनी अपने पूरे चेहरे का मेकअप शुरू करती हैं। मेकअप में वह अपना पर्सदीदा विंग आईलाइनर लगाती हैं। ग्लैम के लिए कोरल ब्लश, और स्मूथ लिप्स के लिए न्यूड लिपस्टिक का यूज करती हैं।



HOW TO: GLASS SKIN

किसान
आंदोलन

परिवहन विशेष न्यूज

किसान आंदोलन के चलते सिंधु बार्डर पर रात में सीमेंट के कई नए बैरिकेड्स लगा दिए हैं। वहीं टीकरी बार्डर पर रातोंरात दीवार खड़ी कर दी गई है। सीमा पूरी तरह से सील है। दिल्ली से हरियाणा व हरियाणा से दिल्ली आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। साथ ही लोग दिल्ली-नोएडा और दिल्ली-गाजियाबाद के बॉर्डर भी सील हैं।

नई दिल्ली। किसान आंदोलन के दूसरे दिन पर भी पुलिस किसी तरह की कोताही नहीं करना चाहती। बीते कई दिनों से इस आंदोल को लेकर सुरक्षा तैयारियों में जुटी दिल्ली पुलिस मंगलवार से ही कई गुना ज्यादा सख्ती और सतर्कता बढ़ा चुकी है।

सिंधु, टीकरी, गाजीपुर व औचंदी बार्डर समेत सभी छोटी-बड़ी सीमाओं पर कई दिनों से लोहे के बैरिकेड, जसी बैरियर, कंटीले तारों के बैरियर, पत्थर व रेत से भरे डंपर, कंटेनर, क्रेन, रोड रोलर, सड़क पर बिछाए जाने वाले नुकीले कांटियों के बैरियर, वाटर केनन, ऑसू गैस छोड़े जाने वाले वाहन आदि को जमा करने का काम शुरू कर दिया था।

अब इनमें से कई जगह पर बैरिकेडिंग काफी हद तक स्थायी कर दी गई है जो किसी स्पष्ट नतीजे के बाद ही हट सकेगी। गाजीपुर, सिंधु, टीकरी सहित अन्य सीमाओं पर सड़कों के दोनों तरफ की सर्विस रोड पर रविवार देर रात ही कई स्तर के बैरिकेड लगा पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे।

छह सरकारी अस्पतालों में घटिया वस्तुओं की आपूर्ति करनेवाले 10 आरोपी गिरफ्तार, ACB ने की कार्रवाई

दिल्ली के छह सरकारी अस्पतालों में खराब गुणवत्ता वाली वस्तुओं की आपूर्ति करने वाली कंपनियों के सात निर्माताओं और तीन प्रयोगशाला प्रबंधकों को गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने यह कार्रवाई की है। इस मामले में लोकनायक अस्पताल दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल गुरु तेग बहादुर अस्पताल लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल एसजीए और जेएसएसएच अस्पताल के डॉक्टरों अधिकारियों और स्टोर कीपर की मिलीभगत सामने आई है।

नई दिल्ली। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने दिल्ली के छह सरकारी अस्पतालों में खराब गुणवत्ता वाली वस्तुओं की आपूर्ति करने वाली कंपनियों के सात निर्माताओं और तीन प्रयोगशाला प्रबंधकों को गिरफ्तार किया है। प्रयोगशाला मालिकों व प्रबंधकों ने घटिया वस्तुओं के मामले में नकली और जाली प्रयोगशाला रिपोर्ट प्रदान की थी। इस मामले में लोकनायक अस्पताल, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, गुरु तेग बहादुर अस्पताल, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल, एसजीए और जेएसएसएच अस्पताल के डॉक्टरों, अधिकारियों और स्टोर कीपर की मिलीभगत सामने आई है। वास्तविक वस्तुओं को प्राप्त किए बिना अस्पतालों द्वारा जाली रसीदें जारी की गई थी। एसीबी के संयुक्त आयुक्त मधुर वर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सतर्कता शाखा की छह टीमों ने 18 अगस्त 2023 को दिल्ली सरकार के अस्पतालों का दौरा कर रोलड बैंडेज, आइवी सेट आदि के नमूने एकत्र कर जीएनसीटी-अनुमोदित प्रयोगशालाओं में भेजा था। इनमें से अधिकांश नमूने परीक्षण के दौरान घटिया या विफल साबित हुए। ये सैंपल काटन बैंडेज, डीलक्स इन्फ्यूजन सेट, रोलड बैंडेज, एब्जाबैट काटन आईपी, लेटेक्स एग्जामिनेशन ग्लव्स (सेनोमिक), वेल्प्रो डिस्पोजल सर्जिकल रबर ग्लव्स, सेफाइजर हैंड सैनिटाइजर, इन्फ्यूजन सेट से संबंधित हैं।

बरवाला गांव वालों ने हाईवे के साथ बनी दीवार को हटाकर मांगा रास्ता



परिवहन विशेष। एसडी सेटी।

दिल्ली के गांव बरवाला के पास निर्माणधीन हाईवे अर्बन एक्सटेंशन रोड नंबर-2 (यूईआर-2) की वजह से इसके साथ स्थाई दीवार खड़ी की जा रही है। इससे सैकड़ों गांव वालों की आवाजाही, से लेकर इमरजेंसी में पुलिस व एम्बुलेंस तक का रास्ता ब्लॉक होने से गुस्साएं, सैकड़ों ग्रामीणों ने हाईवे के नीचे धरना-प्रदर्शन कर नेशनल हाईवे पर चढ़ने के लिए दो रास्ते दिए

जाने की मांग की। इस धरना-प्रदर्शन का नेतृत्व 'बरवाला पंचायत- पंचायत-360 और राष्ट्र हितैषी मजदूर परिषद' ने किया। पंचायत सुप्रीमो एनपीपीएस राम किशन पुनिया एवं परिषद के अध्यक्ष दलीप कुमार बरवाला ने बताया कि निर्माणधीन हाईवे के बनने पर उसके बराबर से दीवार बनाने से गांव वालों के वाहन, ठेला, कीकल, आपातकालीन जिनमें पुलिस, एम्बुलेंस जैसी आवश्यक सुविधाएं गांव के आधे हिस्से नहीं

आ पाएंगे। परिषद समेत पंचायत व गांव वालों की मांग है कि उन्हें हाईवे पर चढ़ने के लिए दो रास्ते मुहैया कराए जाएं। परिषद के अध्यक्ष दलीप कुमार बरवाला के मुताबिक जब इस बावत समेत राष्ट्रपति को ज्ञापन देने की और बड़े तो पुलिस ने प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा धारा 144 का हवाला देकर पुलिस ने गांव वालों को रोक दिया गया।

अरविंद केजरीवाल को ED ने भेजा छटा समन, शराब घोटाले में 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया



अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने फिर से समन भेजा गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री को छठी बार समन भेजा है। इससे पहले बार-बार समन को नजरअंदाज करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने के लिए समन जारी किया था।

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को छठा समन जारी किया है। आम आदमी पार्टी

(आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 19 फरवरी को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।

17 फरवरी को कोर्ट में पेशी

दिल्ली की राज्ज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में भेजे गए समन की अवज्ञा करने के लिए ईडी द्वारा दायर एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पिछले सप्ताह केजरीवाल को 17 फरवरी को उसके समक्ष पेश होने के लिए कहा था। अदालत ने कहा था कि केजरीवाल प्रथमदृष्टया इसका अनुपालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं।

इस मामले में ईडी द्वारा भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के पूर्व अधिकारी को भेजा गया यह छठा समन है। इससे पहले उन्हें इस साल दो फरवरी, तीन जनवरी 18 जनवरी और 2023 में दो नवंबर एवं 21 दिसंबर को बुलाया गया था। मुख्यमंत्री ने हमेशा इन नोटिस को अवैध बताया है और पेश नहीं हुए हैं। उन्होंने इन समन

को राजनीति से प्रेरित बताया था। केजरीवाल ने ईडी की कार्रवाई के पीछे के मकसद पर भी सवाल उठाया था।

ईडी ने केजरीवाल पर लगाया ये आरोप बता दें कि आबकारी घोटाले मामले में ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया गया है। एजेंसी ने कहा है कि आरोपी अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 की तैयारी के संबंध में उसके संपर्क में थे। ईडी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया था कि आप ने अपने गोवा चुनाव अभियान में लगभग 45 करोड़ रुपये की अपराध की आय का इस्तेमाल किया था।

उधर आम आदमी पार्टी आबकारी घोटाले को फर्जी करार देती रही है। आप का आरोप है कि इस मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को फर्जी तरीके से जेल में डाला हुआ है।

आतिशी-सौरभ भारद्वाज... दिल्ली में इन पर दांव लगा सकते हैं अरविंद केजरीवाल

आप ने अब साफ कर दिया है कि वह दिल्ली की छह सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। इससे यह साफ है कि आप इन सीटों पर जल्द ही अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। संभावना है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने विधायकों पर दांव लगा सकती है। गोवा और गुजरात में प्रत्याशियों की घोषणा के बाद यह संभावना और बढ़ गई है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने विधायकों पर भी लोकसभा चुनाव में दांव लगा सकती है। गोवा और गुजरात में वर्तमान में विधायकों को लोकसभा चुनाव में उतार देने के बाद इस बारे में संभावनाएं बढ़ गई हैं। दिल्ली में उत्तरी पश्चिमी दिल्ली सीट के लिए

आप के पास दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष राखी बिड़ला जैसा नाम है।

2019 में आतिशी ने लड़ा था चुनाव

वहीं अन्य सीटों के लिए दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज, जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती और दक्षिणी सीट के परिपेक्ष में तुगलकाबाद से विधायक सहाराम पहलवाल जैसे नाम हैं। आतिशी पिछले लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली सीट से चुनाव मैदान में उतर भी चुकी हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी अपने चार विधायकों को चुनाव मैदान में उतारने की रणनीति बना रही है।

फिल्म अभिनेता के नाम पर विचार

इसके अलावा दो प्रत्याशियों में फिल्म अभिनेता और पूर्व नौकरशाहों के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। आप ने अब साफ कर दिया है कि वह दिल्ली की छह सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। गठबंधन को लेकर हीलाहवाली पर



कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए यह बंधी बता दिया है कि दिल्ली में उसकी स्थिति एक सीट देने के लायक भी नहीं है, मगर आईएनडीआईए गठबंधन के धर्म को निभाते हुए एक सीट देगी।

10 साल बीजेपी के पास हैं 7 सीटें इससे यह साफ है कि आप इन सीटों

पर जल्द ही अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। दिल्ली की स्थिति की बात करें तो दिल्ली की सातों सीटें पिछले 10 साल से भाजपा के पास हैं। पिछले लोकसभा चुनावों में भाजपा ने 2014 और 2019 के संसदीय चुनावों में सभी सात लोकसभा सीटें भारी अंतर से जीतीं। 2019 में



भाजपा उम्मीदवारों को कांग्रेस और आप उम्मीदवारों की संयुक्त संख्या से अधिक वोट मिले।

पिछली बार की तरह ही इस बार भी आप का कांग्रेस के साथ गठबंधन होने की संभावना अब न के बराबर है। आप की मानें तो उसकी पिछले लोकसभा चुनाव से

अब स्थिति सुधरी है। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और दिल्ली नगर निगम में उनकी पार्टी सत्ता में आई है। आप नेताओं की मानें तो यह चुनाव पिछले सालों की तुलना में अलग होगा।

आप (आम आदमी पार्टी) ने किया हाई कोर्ट की ज़मीन पर कब्जा, शीर्ष अदालत ने कहा किसी को कानून..

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी पर हाल ही में एक बड़ा आरोप लगाया गया है। पार्टी पर यह आरोप है कि उसने दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन हड़पकर उस पर अपना दफ्तर बनाया है। आप के इस कदम पर देश की सर्वोच्च अदालत ने भी नाराजगी जताते हुए दिल्ली सरकार को यह जमीन खाली करने के आदेश दिया है और कहा कि किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं होगी। ऑफिस दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई जमीन पर है। यह बंगला पहले दिल्ली के परिवहन मंत्री का आवास हुआ करता था।

आदमी पार्टी की सरकार—लेकिन बाद में पार्टी ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार को इस हरकत को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। आखिर कोई राजनीतिक पार्टी कोर्ट की जमीन पर कैसे रह सकती है। उन्होंने दिल्ली सरकार से सोमवार तक जमीन को वापस देने के लिए कहा है। सुनवाई के दौरान किसी पार्टी का नाम नहीं लिया गया। लेकिन जानकारी के मुताबिक, वकीलों ने पुष्टि की है कि वह आम आदमी पार्टी है।



राजनीतिक पार्टी का कब्जा—

चीफ जस्टिस डिवाइस चंद्रचूड़ और मनोज मिश्रा की पीठ ने इस बात पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि 6 साल पहले आवॉर्डित जमीन पर अब भी एक राजनीतिक पार्टी का कब्जा है और यह जमीन जिला अदालत में न्यायिक बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए दी गई है। अदालत का कहना है कि यह जमीन जजों के लिए बंगले बनाने के लिए जरूरी नहीं है। बल्कि कोर्ट को सुविधाएं देने और अदालत कक्ष बनाने के लिए है। निर्देश में कहा गया कि अदालत को इस जमीन पर बिना किसी अतिक्रमण के कब्जा दिया जाए।

सरकार को बहुत से निर्देश—

इसके साथ ही दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, दिल्ली लोक निर्माण विभाग के सचिव और दिल्ली सरकार के वित्त सचिव को शीर्ष न्यायालय ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार जनरल के साथ बैठक स्थिति से अवगत कराने को कहा। इस मामले में पिछली सुनवाई पर भी शीर्ष अदालत ने राजधानी में न्यायिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के संबंध में दिल्ली सरकार को बहुत से निर्देश दिए थे।

घर के सामने गाली-गलौज का विरोध करना पड़ा महंगा, संसद के कर्मचारी से मारपीट; पथराव भी किया

गाजियाबाद के लोकप्रिय विहार में घर के बाहर खड़े होकर गाली-गलौज करने से रोकने पर संसद के कार्यालय सहायक से युवकों ने मारपीट की। आरोपियों ने कर्मचारी के कपड़े तक फाड़ दिए। वह भाग कर घर में घुसे तो युवकों ने पथराव कर दिया। पुलिस ने 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।

गाजियाबाद। थाना क्षेत्र के लोकप्रिय विहार में घर के बाहर खड़े होकर गाली-गलौज कर रहे युवकों का विरोध करना संसद के कार्यालय सहायक को भारी पड़ गया। आरोपित ने मारपीट की और कपड़े फाड़ दिए। वह भाग कर घर में घुसे तो पथराव कर दिया। पुलिस ने 20 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। संसद में कार्यालय सहायक लोकप्रिय विहार खोड़ा के खेलेश यादव ने बताया कि 12 फरवरी की रात करीब साढ़े 10 बजे उनके घर के बाहर खड़े होकर 15 से 20 लड़के गाली गलौज और अपद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। वह और उनके परिवार के लोग घर में थे। उन्होंने बाहर निकलकर युवकों से गाली गलौज नहीं करने की बात की। यह बात युवकों को नागवार गुजरी। युवक उनसे अपद्रवा करने लगे। विरोध करने पर मारपीट कर कपड़े फाड़ दिए। वह भागकर अपने घर में घुसे गए। आरोप है कि युवकों ने उनके घर पर पथराव कर दिया। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोगों मेंके पर एकत्र होने लगे। यह देखकर आरोपित जान से मारने की धमकी देकर भाग गए।

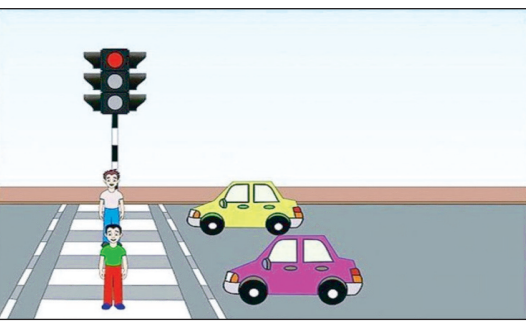
सत श्री अकाल प्रणाम वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फ़तेह चरण स्पर्श

परिवहन विशेष न्यूज़
नई दिल्ली। सरदार देवेंद्र सिंह सदस्य स्टेट रोड सेफ्टी कार्डसिल हरियाणा सरकार,सदस्य मेंबर ऑफ पार्लिमेंट रोड सेफ्टी कार्डसिल भारत सरकार एवं सदस्य रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फरीदाबाद,पलवल,मेवात,सदस्य नीति आयोग भारत सरकार एवं फिट इंडिया भारत सरकार एवं एजीक्यूटिव सदस्य इंडियन रेडक्रॉस सोसइटी फरीदाबाद, मोटीवेटर सदस्य ब्लड डोनेशन इंडियन रेडक्रॉस सोसइटी हरियाणा एवं सदस्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद, पलवल,मेवात,सदस्य स्पेशल टास्क फोर्स स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा सरकार, सदस्य चीफ मिनिस्टर गुड गवर्नैस फरीदाबाद, सदस्य पॉलिथोन अभियान म्युन्सिपल कोर्परशन फरीदाबाद,रोड सेफ्टी ऑफिसर हरियाणा पुलिस,सदस्य स्मार्ट सिटी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट फरीदाबाद,सीनियर रेल वार्डन जनरल रेलवे पुलिस हरियाणा,फाउंडर रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन(रंजि.) एवं फाउंडर चहदी कला रहे खालसा हरियाणा,54 टाइम्स अपना रक्तदान सड़क सुरक्षा एवं थैलेसेमिआ बच्चों के लिए स्वं ही दान करना स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड साल 2009 से

कोटा में छात्रों की आत्महत्याओं की घटनाएं शहर के दामन पर दाग लगा रही हैं

रमेश सर्राफ धमोरा
राजस्थान का कोटा शहर देश में कोचिंग का सबसे बड़ा केन्द्र बन चुका है। यहां प्रतिवर्ष लाखों छात्र कोचिंग करने के लिए आते हैं। जिससे कोचिंग संचालकों को सालाना कई हजार करोड़ रुपए की आय होती है। हालांकि कोटा आने वाले सभी छात्र मेडिकल व इंजीनियरिंग परीक्षा में सफल नहीं होते हैं। कोटा में एक बार फिर कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड का मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले स्टूडेंट शुभकुमार चौधरी (16) ने सोमवार रात फंदे पर लटककर जान दे दी। डीएसपी भवानी सिंह ने बताया कि स्टूडेंट 12 वीं में पढ़ाई करता था। सोमवार रात जेईई की रिजल्ट आया था। सुबह उसने पैरेंट्स का फोन नहीं उठाया तब वार्डन को कॉल किया। वार्डन ने गेट को धक्का देकर खोला तो स्टूडेंट पंखे पर लटक हुआ था। इस साल कोटा में सुसाइड का यह चौथा मामला है। इसके अलावा 2 फरवरी को गोंडा के नूर मोहम्मद (27) ने, 31 जनवरी को कोटा के बोरखेड़ा की निहारिका (18) ने, 24 जनवरी को मुरादाबाद के मोहमद जैद (19) ने आत्महत्या की थी। राजस्थान का कोटा शहर देश में कोचिंग का सबसे बड़ा केन्द्र बन चुका है। यहां प्रतिवर्ष लाखों छात्र कोचिंग करने के लिए आते हैं। जिससे कोचिंग संचालकों को सालाना कई हजार करोड़ रुपए की आय होती है। हालांकि कोटा आने वाले सभी छात्र मेडिकल व इंजीनियरिंग परीक्षा में सफल नहीं होते हैं। मगर देश की शीर्षस्थ मेडिकल व इंजीनियरिंग संस्थानों में भर्तित्त होने वाले छात्रों में कोटा के छात्रों की संख्या काफी होती है। इसी कारण अभिभावक अपने बच्चों को

साल 2024 :सदस्य तीन नेशनल अवॉर्ड साल 2012 -साल 2013 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रेड क्रॉस सोसइटी फरीदाबाद एवं सिंडिकेट लीड बैंक जिला फरीदाबाद, एक बार हरियाणा सरकार के गवर्नर से सम्मानित होना , 5 बार चीफ मिनिस्टर हरियाणा सरकार के द्वारा सम्मानित होना ,पाँच बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिला फरीदाबाद से सम्मानित होना, पाँच बार से ज्यादा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हरियाणा सरकार से सम्मानित होना, एक बार कृषि मंत्री हरियाणा सरकार से सम्मानित होना,पाँच बार से ज्यादा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद एवं पलवल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट से सम्मानित होना ,13 से ज्यादा डिप्टी कमिश्नर,एसडीएम एवं पुलिस कमिश्नर जिला फरीदाबाद से सम्मानित होना,13 बार इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद से सम्मानित होना, हेला इंडिया लिमिटेड कंपनी से पाँच बार सम्मानित होना अन्य फरीदाबाद ,पलवल, दिल्ली शहर की सभी सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं से एवं फरीदाबाद शहर से बाहर एनसीआर के क्षेत्र की कई संस्थाओं से कई बार सम्मानित होना कार्य क्षेत्र:मैनेजर आईएसआर डॉक्टर ओ पी
--

	सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया , बीएसएफ, पंजाब स्टेट हेल्थ सर्विस , पंजाब पुलिस,पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, गुड ईयर इंडिया, लिमटेड ,टीकम शाह इंडिया लिमिटेड , जेसीबी इंडिया लिमिटेड , हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड ,एबीबी इंडिया लिमिटेड , आईबीएम दक्ष , एक्सिकन इंडिया लिमिटेड ,हीरो हौडा इंडिया, गैलिलिओ इंडिया लिमिटेड , एचसीएल डेल पेरोट सिस्टम नोएडा, ELL , एमएमटीसी MMTC, गति कार्गो, बिरला सॉफ्ट नोएडा , Techspan India, RMSI सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड , डेंटल इंडिया , SPIU भोपाल यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश एवं अन्य प्राइवेट एवं सरकारी कंपनी में अपनी कंप्यूटर की जगह जगह पर सेवा देना वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फ़तेह रब है ता सब है करे करावे आपे आप मानस के कुश नहीं हाथ जीवन का निचोड़ यही है सच जीवन का : आओ हम सभी एक साथ मिलकर चले अपने अपने गाँव की ओर सरदार देवेंद्र सिंह मोबाइल नंबर :9643283909
--	--

	रूप से अधिक सक्षम नहीं होते हैं। अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाने के लिए वह लोग विभिन्न स्तरों पर पैसों की व्यवस्था कर बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा भेजते हैं। कोटा आने वाले छात्रों को पता है कि उनके अभिभावकों ने कितनी मुश्किल से कोचिंग लेने के लिए उन्हें कोटा भेजा है। ऐसे में यदि वह सफल नहीं होंगे तो उनके अभिभावक जिंदगी भर कर्ज में दबे रह जाएंगे। यही सोचकर छात्र हमेशा मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता रहता है। इसके अलावा यहां पढ़ने वाले छात्रों पर पढ़ाई का भी बहुत अधिक दबाव रहता है। यहां के कोचिंग संस्थानों में कई शिफ्टों में अलग-अलग बैच में पढ़ाई होती है। यहां पढ़ने वाले छात्रों पर मेडिकल या इंजीनियर की परीक्षा में अच्छे नंबर हासिल करने को लेकर अभिभावकों व कोचिंग संस्थानों का दबाव होता है। कोचिंग संस्थान भी अच्छा परिणाम दिखाने के
--	--

सूरजपुर थाना क्षेत्र के साकीपुर गांव के पास 26 वर्षीय स्कूल शिक्षक को कथित तौर पर कुछ व्यक्तिगत विवाद के कारण दो लड़कों ने गोली मार दी। नाम पृछने के बाद मारी गोली यह घटना सुबह करीब नौ बजे के आसपास हुई जब शिक्षक और लड़के साकीपुर गांव में स्कूल से करीब 500 मीटर दूर सड़क पर बातचीत कर रहे थे। बाइक सवार दो लड़कों में एक हमलावर ने हेलमेट लगा रखा था। ग्रेटर नोएडा।सूरजपुर थाना क्षेत्र के साकीपुर गांव के पास बाइक सवार दो लड़कों ने 26 वर्षीय शिक्षक को गोली मार दी। इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक, गोली शिक्षक के कान के नीचे लगी है। गोली लगने से घायल शिक्षक र्कीब हुसैन को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद डीसीपी सेंट्रल नोएडा सुनीति ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित स्वजन से बातचीत कर उन्हें हर संभव कार्रवाई का आश्वासन दिया है। रकीब हुसैन मॉडन पब्लिक स्कूल में अध्यापक हैं। वह घर पर भी ट्यूशन पढ़ाते हैं। एक ने लगाया हुआ था हेलमेट बाइक सवार दो लड़कों में एक हमलावर ने हेलमेट लगा रखा था। 26 वर्षीय स्कूल शिक्षक

लगे। आज कोटा शहर की पूरी अर्थव्यवस्था इन कोचिंग संस्थानों पर ही निर्भर है। शहर के हर चौक-चौराहों पर छात्रों की सफलता से अटे पड़े बड़े-बड़े हॉर्डिंग्स बताते हैं कि अब कोटा में कोचिंग ही सब कुछ है। यह सही है कि कोटा में सफलता की दर तीस प्रतिशत से ऊपर रहती है। देश के इंजीनियरिंग और मेडिकल के प्रतियोगी परीक्षाओं में टाप टेन में पांच छात्र कोटा के रहते हैं। मगर उसके साथ ही कोटा में एक बड़ी संख्या उन छात्रों की भी है जो असफल हो जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक कोटा के कोचिंग मार्केट का सालाना आठ हजार करोड़ का टर्नओवर है। कोचिंग सेंटरों द्वारा सरकार को सालाना 500-700 करोड़ रूपये से अधिक टैक्स के तौर पर दिया जाता है। कोटा में देश के तमाम नामी गिरामी संस्थानों से लेकर छोटे-मोटे 200 कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। यहां तक कि दिल्ली, मुंबई के साथ ही कई विदेशी कोचिंग संस्थाएं भी कोटा में अपना सेंटर खोल रही हैं। लगभग ढाई लाख छात्र इन संस्थानों से कोचिंग ले रहे हैं। कोटा में सफलता की बड़ी वजह यहां के शिक्षक हैं। आईआईटी और एम्स जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेजों में पढ़ने वाले छात्र बड़ी-बड़ी कम्पनियों और अस्पतालों की नौकरियां छोड़कर यहां के कोचिंग संस्थाओं में पढ़ा रहे हैं। तनख्वाह ज्यादा होने से कोटा शहर में 75 से ज्यादा आईआईटी पास छात्र पढ़ रहे हैं। कोटा में बढ़ती आत्महत्याओं की घटनाओं से चिंतित सरकार हरकत में आई है। कोटा में कोचिंग करने वाले छात्रों के लिए अलग से पुलिस थाना खोला गया है। हॉस्टल के कमरों में ऐसे पंखे लगाए गये हैं जिन पर यदि कोई लटकने की कोशिश करेगा तो उस पर लगी डिवाइस में लगा सायरन बजने लगेगा। सरकार ने छात्रों के मानसिक तनाव के विस्तृत अध्ययन के लिए मनोचिकित्सकों की एक टीम भी बनाई है जो छात्रों से मिलकर आत्महत्याओं के कारणों की जांच करेगी। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कहा था कि कोटा में बच्चों की	को कथित तौर पर कुछ व्यक्तिगत विवाद के कारण दो लड़कों ने गोली मार दी। नाम पृछने के बाद मारी गोली यह घटना सुबह करीब नौ बजे के आसपास हुई, जब शिक्षक घर से स्कूल जा रहे थे, इस दोाना शिक्षक से करीब 500 मीटर पहले बाइक सवार दो बदमाशों ने उनको रोक लिया। नाम पृछने के बाद गोली मार दी। पुलिस ने आशंका जाहिर की है कि महिला मित्र के चक्कर में घटना को अंजाम दिया गया है। घटना के पर्दाफाश में पुलिस की तीन टीमें लगाई गई हैं। कान को छूते हुईं निकली गोली... एक गोली शिक्षक के कान के निचले हिस्से को छूती हुई निकल गई, घटना के बाद कोर्ट ने अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत ख़वरे से बाहर बताई जा रही है। बता दें कि र्कीब हुसैन सूरजपुर इलाके में चांद वाली मस्जिद गली में रहते हैं और वारदात के वक़्त वह सुशाल मॉडर्न स्कूल जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में करीब 17 साल की उम्र के दो लड़के उससे बात करने आए और बाद में उन पर गोलियां चला दीं। पुराने विवाद को लेकर मारी गोली पुलिस का कहना है कि वे दोनों पक्षों के बीच पिछले विवाद के लिंक सहित सभी एंगल से मामले की जांच कर रहे हैं और हमले में शामिल दोनों लड़कों की तलाश शुरू कर दी है।
--	---

महिंद्रा थार 5 डोर अलॉय व्हील्स के साथ मारेगी एंट्री! स्पाई शॉट्स में दिखी झलक

पिछले काफी समय से Thar के 5-डोर वर्जन की टेस्टिंग कर रही है। नवीनतम स्पाई शॉट्स से पता चलता है कि थार 5-डोर में अलॉय व्हील के एक नए सेट का उपयोग किया जाएगा जो थार 3-डोर से बड़े हैं। महिंद्रा अभी अपनी इस ऑफरोड एसयूवी में 18-इंच यूनिट का उपयोग करता है जबकि 5-डोर थार डायमंड-कट फिनिश के साथ 19-इंच यूनिट का उपयोग करेगी।

नई दिल्ली। पिछले काफी समय से Thar के 5-डोर वर्जन की टेस्टिंग कर रही है। नई एसयूवी के इस साल के अंत में विक्री पर आने की उम्मीद है। नवीनतम स्पाई शॉट्स से पता चलता है कि 5-Door Mahindra Thar में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव करेगा। इससे 5-दरवाजे वाले संस्करण को 3-दरवाजे वाले मॉडल से अलग करने में मदद मिलेगी। आइए, इसके बारे में जान लेते हैं।

नए स्पाई शॉट्स में क्या दिखा ?
नवीनतम स्पाई शॉट्स से पता चलता है कि थार 5-डोर में अलॉय व्हील के एक नए सेट का उपयोग किया जाएगा जो थार 3-डोर से बड़े हैं। महिंद्रा अभी अपनी इस ऑफरोड एसयूवी में 18-इंच यूनिट का उपयोग करता है, जबकि 5-डोर थार डायमंड-कट फिनिश के साथ 19-इंच यूनिट का उपयोग करेगी।
Mahindra Thar 5-door



का डिजाइन
अलॉय व्हील के अलावा, थार 5-डोर में अन्य बदलाव भी हैं। हेडलैंप अब एलईडीएस होंगे और नए एलईडी डेटाइम रनिंग लैंप भी होंगे। रियर टेल लैंप यूनिट भी अब नई हैं और इनमें एलईडी तत्वों को फिर से डिजाइन किया गया है। इसके बाद

फ्रंट ग्रिल आती है, जिसे बदल दिया गया है और अब रियर डोर हैंडल को सी-पिलर पर रखा गया है।
इंटीरियर
इंटीरियर लेआउट ज्यादातर वही रहेगा, लेकिन अब इसमें कुछ अपडेट होंगे। उदाहरण के लिए, स्टीयरिंग व्हील

को XUV 700 से लिया जाएगा। डैशबोर्ड में सबसे बड़ा बदलाव नया इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा, जिसे XUV 400 से आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन इसमें ईवी से संबंधित कुछ सुविधाएं नहीं होंगी। नया इंफोटेनमेंट सिस्टम मौजूदा से बड़ा है और नए यूजर इंटरफेस पर चलता है। यह

वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले को सपोर्ट करेगा।
5-दरवाजे वाली थार को हाल ही में लंबाई में हाई एल्टीट्यूड पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। ऑटोमोबाइल निर्माता अक्सर अपने वाहनों का परीक्षण सभी प्रकार के वातावरण में करते हैं।



सिर और श्रोणि को अच्छी सुरक्षा, छाती को सीमांत सुरक्षा और पेट को पर्याप्त सुरक्षा मिलती है।

2024 Tata Nexon के सेफ्टी फीचर्स

नेक्सॉन स्टैंडर्ड रूप में पैदल यात्री सुरक्षा के लिए UN127 और GTR9 आवश्यकताओं को पूरा करती है। मॉडल ग्लोबल एनसीएपी की ईएससी आवश्यकताओं का भी अनुपालन करती है और सभी बैठने की स्थिति में सीटबेल्ट अनुस्मारक प्रदान करता है।

सेफ्टी फीचर्स के संदर्भ में नेक्सॉन 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ISOFIX माउंट, रियर पार्किंग सेंसर, टिल्ट्स और कोलैप्सिबल स्टीयरिंग, सेंट्रल लॉकिंग और हिल होल्ड कंट्रोल के साथ आती है।

Tata की सभी SUVs हैं 5-स्टार

अभी तक, सभी Tata SUVs को क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली हुई है। इस माइलस्टोन को अचीव करने पर टिप्पणी करते हुए, टाटा मोटर्स पैरेंजर व्हीकल्स के मुख्य उत्पाद अधिकारी, मोहन सावरकर ने कहा-

सुरक्षा हमारे डीएनए में निहित है और हमें नई नेक्सॉन के लिए ग्लोबल एनसीएपी से 5-स्टार रेटिंग अर्जित करने पर गर्व है।

हीरो मैवरिक 440 भारतीय बाजार में 1.99 लाख रुपये की कीमत पर लॉन्च, 15 मार्च तक बुक करने पर मिलेगा ये खास ऑफर

Hero MotoCorp ने अपनी बहुप्रतीक्षित प्रीमियम बाइक Mavric 440 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। डिजाइन की बात करें तो Mavric 440 नियो-रेट्रो एलीमेंट के साथ एक मस्कुलर फ्यूल टैंक वाली रोडस्टर है। Hero MotoCorp फ्यूल टैंक श्राउड और यहां तक कि फैंडर के लिए भी धातु का उपयोग कर रहा है। आइए पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। Hero MotoCorp ने अपनी बहुप्रतीक्षित प्रीमियम बाइक Mavric 440 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। ये ब्रांड की फ्लैगशिप मोटरसाइकिल है और इसे तीन वेरिएंट्स - बेस, मिड और टॉप में पेश किया जाएगा। इनकी कीमत 1.99 लाख रुपये, 2.14 लाख रुपये और 2.24 लाख रुपये है। आपको बता दें कि ये सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं।
ऑफर और बुकिंग डिटेल्
जो ग्राहक रुचि रखते हैं वे मोटरसाइकिल की प्री-बुकिंग कर सकते हैं और इसकी डिलीवरी अप्रैल से शुरू होगी। इसके साथ ही कंपनी ने Welcome to Mavrick Club Offer भी पेश किया है। 15 मार्च से पहले Mavric 440 बुक करने वाले ग्राहकों को 10 हजार रुपये

मूल्य की एसेसरीज और मचेंडाइज की एक कस्टमाइज्ड किट मिलेगी।
डिजाइन
डिजाइन की बात करें, तो Mavric 440 नियो-रेट्रो एलीमेंट के साथ एक मस्कुलर फ्यूल टैंक वाली रोडस्टर है। Hero MotoCorp फ्यूल टैंक, श्राउड और यहां तक कि फैंडर के लिए भी धातु का उपयोग कर रहा है। मोटरसाइकिल पर लाइटिड इयूटी के लिए एलईडी का इस्तेमाल किया गया है। Mavric 440 में हीरो ने एक डिजिटल स्पीडोमीटर पेश किया है, जो नेगेटिव डिस्प्ले का उपयोग करता है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है।
इंजन
Mavric 440 में वही इंजन है जो HD X 440 को दिया गया था। ये इंजन 6,000 आरपीएम पर 27 बीएचपी की अधिकतम पावर और 4,000 आरपीएम पर 36 एनएम का पीक टॉर्क आउटपुट देता है, जो कि X 440 से 2 एनएम कम है। ऑन इयूटी गियरबॉक्स एक 6-स्पीड यूनिट है, जिसमें स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच मिलता है।
हीरो मोटोकॉर्प के अनुसार, मावरिक 440 उनके द्वारा बनाई गई सबसे प्रीमियम मोटरसाइकिल है। हीरो मोटोकॉर्प के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) श्री निरंजन गुप्ता ने कहा कि हमारी प्रीमियम यात्रा अब उन ग्राहकों के लिए बुकिंग के साथ पूरी तरह से जारी है जो मावरिक 440 का बेसवैरी से इंतजार कर रहे हैं।



Kabira KM3000 और KM4000 Electric Bike 1.74 रुपये की कीमत पर लॉन्च, सिंगल चार्ज पर देगी 201 KM की रेंज



KM3000 और KM4000 मॉडल अलग-अलग डिजाइन के साथ आते हैं। कॉस्मेटिक चेंज के अलावा दोनों मॉडलों में एक ही डायमंड स्टील ट्यूब फ्रेम है। मॉडल में एल्यूमिनियम कोर हब मोटर पावरट्रेन की सुविधा है। कंपनी के अनुसार यह तकनीक बाइक्स को 120 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड हासिल करने और केवल 2.9 सेकंड में 0 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सक्षम बनाती है।

नई दिल्ली। गोवा स्थित इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप Kabira Mobility ने दूसरी पीढ़ी की KM3000 और KM4000 Mark-II इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च की है, जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 1.74 लाख रुपये है।
KM3000 और KM4000 मॉडल अलग-

अलग डिजाइन के साथ आते हैं। कॉस्मेटिक चेंज के अलावा दोनों मॉडलों में एक ही डायमंड स्टील ट्यूब फ्रेम है। आइए, इनके बारे में जान लेते हैं।
पावरट्रेन
मॉडल में एल्यूमिनियम कोर हब मोटर पावरट्रेन की सुविधा है। कंपनी के अनुसार, यह तकनीक बाइक्स को 120 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड हासिल करने और केवल 2.9 सेकंड में 0 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सक्षम बनाती है।
चार्जिंग और रेंज
KM3000 और KM4000 Mark-II मॉडल की मुख्य विशेषताओं में 201 किमी की रेंज, 1.5kW का ऑन-बोर्ड चार्जर शामिल है। फॉक्सकॉन द्वारा विकसित 12 किलोवाट इन-हब पावरट्रेन द्वारा संचालित, बाइक 192 एनएम का दावा किया गया अधिकतम टॉर्क प्रदान करती है।

सेफ्टी फीचर्स में डुअल सीबीएस और बड़े डिस्क ब्रेक, शोवा द्वारा फ्रंट टेलीस्कोपिक फोक और पीछे एक मोनोशॉक यूनिट शामिल हैं।
कीमत
KM3000 और KM4000 Mark-II मॉडल की कीमत क्रमशः 1.74 लाख रुपये और 1.76 लाख रुपये, एक्स-शोरूम है। इन मॉडलों के लिए टेस्ट राइड चयनित स्थानों पर उपलब्ध होंगी, जिनकी डिलीवरी कंपनी के डीलरशिप नेटवर्क के माध्यम से मार्च 2024 से शुरू होने वाली है।
राइडिंग मोड
दोनों बाइक में रात के समय बेहतर राइडिंग के लिए प्रोजेक्टर हेडलाइट और अतिरिक्त स्पेस के लिए एक स्टायलिश फ्रंक है। राइडर की सुविधा के लिए इको, स्पोर्ट्स, सिटी, पार्किंग और रिवर्स जैसे पांच राइडिंग मोड भी उपलब्ध हैं।

इस देश में नहीं आ सकेंगी पेट्रोल-डीजल से चलने वाली विदेशी गाड़ियां, इंपोर्ट पर लगाया प्रतिबंध

परिवहन और रसद मंत्री अलेमु सिमने ने इथियोपिया के रसद मास्टर प्लान की घोषणा की जिसमें देश में Green Transport समाधान लागू करना शामिल होगा। मंत्री इथियोपियाई संसद में शहरी विकास और परिवहन स्थायी समिति को प्रस्तुत कर रहे थे। इथियोपिया हाल के वर्षों में अधिक ईवी अपनाने पर जोर दे रहा है। आइए पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। Ethiopia ने पेट्रोल और डीजल कारों के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इथियोपिया ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। पूर्वी अफ्रीकी राष्ट्र वित्तीय उथल-पुथल से जूझ रहा है और विदेशी मुद्रा संसाधनों को सीमित करने के लिए ये निर्णय लिया गया है।
Green Transport समाधान लाया इथियोपिया
परिवहन और रसद मंत्री अलेमु सिमने ने इथियोपिया के रसद मास्टर प्लान की घोषणा की जिसमें देश में Green Transport समाधान लागू करना शामिल होगा। मंत्री इथियोपियाई संसद में शहरी विकास और परिवहन स्थायी समिति को प्रस्तुत कर रहे थे। नई नीति इथियोपिया में आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहनों के आयात को सीमित करती है, लेकिन यह वहां के लोगों के लिए समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं करती है।
आम लोगों की पहुँच से बाहर
विश्व स्तर पर इलेक्ट्रिक कारें महंगी बनी हुई हैं और बड़ी संख्या में इथियोपियाई नागरिकों के लिए ईवी अभी भी वित्तीय रूप से काफी मुश्किल



सौदा होने वाली है। इथियोपिया में वाहन खरीदने में सक्षम लोगों की आबादी बहुत कम है। सिमने ने आगे कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक कारों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि प्रतिबंध स्थायी रहेगा या अस्थायी और क्या पहले से ही पारगमन में मौजूद वाहन नई नीति से प्रभावित होंगे।
Ethiopia में है इनका कारोबार
वर्तमान में, हुंडई, इसुजु, वोक्सवैगन, लाडा और अन्य प्रमुख वाहन निर्माताओं के पास इथियोपिया में स्थानीय असेंबली प्लांट हैं और बाजार के लिए आईसीई और इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन करते हैं। इस कदम से देश के कच्चे

तेल के आयात में भी कमी आनी चाहिए, जो 2023 में \$6 बिलियन (लगभग ₹49,800 करोड़) था। इस कदम से भारत में वाहन निर्माता भी प्रभावित होने की संभावना है, जो अफ्रीकी राष्ट्र को कारों का निर्यात करते हैं।
EV पर सरकार का फोकस
इथियोपिया हाल के वर्षों में अधिक ईवी अपनाने पर जोर दे रहा है। सरकार ने 2022 में कम से कम 4,800 इलेक्ट्रिक बसों और 1.48 लाख इलेक्ट्रिक कारों के आयात का समर्थन करने के लिए 10-वर्षीय योजना लागू की। इसमें ईवी के वैट, अधिभार और उत्पाद शुल्क में भी कटौती की गई है। ये प्रतिबंध कब लागू होंगे इसकी अभी कोई समयसीमा नहीं है।

सोने की सदारत



के तरीके बदल रहे हैं। तकनीक के जरिए धन का लेन-देन होने लगा है। इस कारण भी धन के रूप में सोने की जरूरत कम हुई है। फिर भी किसी देश की आर्थिक समृद्धि और उसकी मुद्रा का प्रमुख आधार सोने की अधिकता ही है। लिहाजा सोने का आयात और खरीद ऐसे कारक हैं, जो देश की आर्थिक उछाल का पर्याय बनते हैं। जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) की बहुत में भी सोने का योगदान आंका जाता है। सोने को विश्व पटल पर 'पी-धातु' की संज्ञा दी गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सोने में आयात के नियमों में ढील देने के कारण कोरोना महामारी और देशबंधी के कालखंड में सोने का आयात अधिक तो हुआ ही, लोगों ने व्यक्तिगत रूप से उसका संग्रह भी खूब किया। यदि इस अनुत्पादक और मृत संपदा में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार खप जाए तो निकट भविष्य में सरकार के सामने विदेशी मुद्रा का संकट खड़ा हो सकता है। एक समय भले ही भारत सोने की चिड़िया कहा जाता हो, लेकिन आज तो उसे अपनी जरूरतों के लिए 95 फीसदी सोना दूसरे देशों से खरीदना होता है। कच्चे तेल के अभाव के आयात में ही सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च होती है। सोना भारतीय परंपरा में धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टियों से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। पूजा-पाठ से लेकर शादी में वर-वधु को सोने के गहने देना प्रतीक्षा और सम्मान का प्रतीक है। जीवन में बुरे दिन आ जाने की आशंकाओं के चलते भी सोना सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति आम आदमी को में खूब है। इसलिए जैसे ही सोना सस्ता होता है, इसकी खरीद बढ़ जाती है। जिसका

अप्रत्यक्ष प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। वित्तमंत्री रहे पी. चिदंबरम को जनता से अपील करनी पड़ी थी कि वह एक साल तक सोना न खरीदें, ताकि देश की माली हालत संभाली जा सके। चिदंबरम ने चेतावनी दी थी कि सोना डॉलर में आयात किया जाता है। इस वजह से व्यापार घाटा खतरनाक तरीके से बढ़ जाता है और रुपए की कीमत भी गिरने लगती है। सोने के आयात के साथ यह धारणा भी बनी हुई है कि इससे चालू खाते के घाटे को कम करने में सहायता मिलती है। आयात और निर्यात के अंतर को व्यापार घाटा माना जाता है। सोने का आयात व्यापार के कई स्तरों को प्रभावित करता है। इसकी बिक्री बाजार के अन्य व्यापारिक क्षेत्रों को भी प्रभावित करती है। भारत सोने का बड़ा बाजार है और इस पर दुनिया की निगाहें टिकी रहती हैं। दूसरे देशों से होने वाले सोने के आयात से ही आभूषण उद्योग चलता-फूलता है। गहने बनाने में कुशल कारीगरों की आजीविका इसी व्यापार से चलती है। सोने का संग्रह और सोने के प्रति विशेष आकर्षण ही वह वजह है, जिसके चलते हर साल 10 टन तक सोने का आयात होता है। मंदिरों में भी अनेक श्रद्धालु सोने का गुप्त या खुला दान करते हैं। मशहूर बाबा अरुण गिरी तो सोने के गहनों से लदे हुए ही देश-विदेश की यात्राएं करते हैं। ये भक्तों से सोना ही दान में लेते हैं। सोने का संग्रह इसलिए भी किया जाता है, क्योंकि भविष्य में इसके दाम बढ़ने की उम्मीद हमेशा बनी रहती है। सोने में जब-जब आयात की शर्तों में कूट और कीमतों में कमी आती है तो इसकी तस्करी भी खूब बढ़

जाती है। अकसर हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर तस्करी का सोना लाने वाले पकड़े जाते हैं। देश में हर महीने तस्करी के जरिए करीब पांच टन सोना आ रहा है। वर्ष 2012-13 में सोने की तस्करी से जुड़े 870 मामले सामने आए थे और सौ करोड़ का सोना जन्त किया गया था। देश के सभी हवाई अड्डों पर तस्करी रोकने के लिए कस्टम विभाग है। इसके अलावा स्थानीय पुलिस भी चौकसी रखती है। देश के बंदरगाहों और समुद्री सीमा पर तस्करी पर निगाह रखने के लिए पुलिस के साथ जलसेना भी है। जिन सफेदपोश जमाखोरों का कालाधन विदेशों में जमा है, वे भी अपने कालेधन को सोने में बदलने लगे हैं। खाड़ी देशों और कालाधन से अर्थव्यवस्था चलाने वाले देशों में ये काला धंधा खूब फल-फूल रहा है। लिहाजा खाड़ी देशों के साथ ही टैक्स हैवन माने गए मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड समेत कई दक्षिण-पूर्वी देश सोने की तस्करी में सहयोग देकर इस धंधे के लिए सोने में सुहागा बने हुए हैं। यह धंधा इसलिए भी उछाल मार रहा है क्योंकि 21वीं सदी के बीते दो दशकों में देश के करीब 3 करोड़ लोगों की समृद्धि बेतहाशा बढ़ी है। इसमें सफेद के साथ काली कमाई भी बड़ी मात्रा में शामिल है। सोना एक अनुत्पादक धातु है, यह केवल व्यक्तिगत वैभव बढ़ाने और भविष्य में आर्थिक सुदृढ़ता से जुड़ी धातु है। देश समेत वैश्वक अर्थव्यवस्था को सोने में आने वाला उतार-चढ़ाव प्रभावित करता है। ऐसे में भारत का सुरक्षित स्वर्ण भंडार के लिहाज से अग्रणी देशों में शामिल होना गौरव की बात है।

संपादक की कलम से

पानी पर टकराव

इस योजना का मकसद पवित्र है, लेकिन मंजिल को लेकर विवाद के कई घाट अली खड्ड के संगम पर बन गए हैं। जल आपूर्ति योजना के नाक में दम करना एक तरफ बिलासपुर जिला का न्याय है, तो दूसरी तरफ सार्वजनिक व्यय की तमाम मंजूरियां सोलन की प्यास बुझाना चाहती हैं। जाहिर है अली खड्ड पीछे कहीं से तो आती होगी और आगे भी जाती होगी। कितनी सदियां पूर्व अली खड्ड बनी या खड्ड अली हो गई, इसे न तो मौजूदा टकराव जानता है और न ही जल शक्ति विभाग के लक्ष्य जानते होंगे। यह मामला प्राकृतिक स्रोतों से जलापूर्ति को सुदृढ़ करने का है और एक राज्य की तस्वीर में आगे बढने का भी है। यह वही राज्य है जिसने शाखड़ा बांध परियोजना से उत्तर भारत के खेतों की हर जरूरत को पानी दिया, तो पौपा बांध के माध्यम से राजस्थान की रेत को हरियाली सौंप दी। हिमाचल की बड़ी बांध परियोजनाओं ने देश को सर्वस्व सौंपा है, तो रेणुका बांध अब दिल्ली की जनता को भरपूर पानी पिलाएगा। कहना न होगा कि जो राज्य देश की जनता के सुकून में अपने योगदान को हमेशा अव्वल रखता आया, आज उसके भीतर बिलासपुर बनाम सोलन के बीच अली खड्ड और उसका पानी आ गया। अकिरल धाराओं से कहीं अधिक तेजी से आपसी सौहार्द की धारा कुंद हो रही है, तो यह छूटना और समझना होगा कि इस परियोजना के आरपार दो जिला और विधानसभा क्षेत्र क्यों खड़े हो गए। दरअसल खड्ड से उठाकर पानी को पड़ोसी अर्की विधानसभा क्षेत्र तक ले जाया जाएगा, ताकि अपने ही प्रदेश की हिमाचली जनता की प्यास बुझे। वहां के ईट-पत्थर मेहनत करते हुए उन बूंदों से अमृत पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी इसी खड्ड से निकलीं अनेक जल परियोजनाओं के सिंहासन भी यहीं बिछे हैं। यानी तकरीबन दो से ढाई दर्जन जलापूर्ति व सिंचाई परियोजनाएं जहां से बिलासपुर व नयनादेवी विधानसभा क्षेत्रों को तृप्त करती थीं, लगभग वहीं सोलन की प्यास बुझाने का अमृत कलश भरा जा रहा है। इसका

वैज्ञानिक आधार, जल शक्ति विभाग की पड़ताल और प्रदेश की जलापूर्ति का समाधान होता दिखाई दे, तो भी परिवेश और पर्यावरण के सवाल पर योजनाओं का यह अर्थ नहीं हो जाता कि कहीं भी आसानी से दोहन किया जाए। अंततः खड्ड को खड्ड की तरह बहने की शक्ति भी तो बचनी चाहिए। जल शक्ति विभाग की योजनाएं अक्सर उसी मिट्टी को खोदना चाहती हैं, जहां से पहले भी कुछ हासिल हुआ। पिछले तीन दशकों से हमारे प्रयोग पानी के सरल मुहाने या भूमिगत पानी के दोहन को सिर्फ मांग की आपूर्ति के नजरिए से देख रहे हैं। आज हिमाचल के लिए एक बड़े क्षेत्र की मांग और संकल्प चाहिए। हमें बरसात में अनावश्यक रूप से बहते पानी का कहीं तो अलग से संग्रहण करना चाहिए, ताकि एक बड़े क्षेत्र की मांग पूरी हो सके। पूरे हिमाचल के जलस्रोतों पर आधारित परियोजनाओं को अब नए सिरे से सुदृढ़ करते हुए उचित जल प्रबंधन के लिए अलग से बांध या सुरंग के जरिए एक नदी से दूसरी नदी या खड्ड तक समाधान ढूंढने होंगे।

हर विद्युत परियोजना अपने उत्पादन से केवल बिजली का प्रबंध करे, इससे कहीं आगे अब इन्हें जलापूर्ति व सिंचाई व्यवस्था से भी जोड़ना होगा। अली खड्ड सर्वप्रथम राज्य की मिलकीयत है और इसके उपयोग की वैज्ञानिक व पर्यावरणीय शर्तों के तहत व आपसी सहमति के जरिए ऐसी परियोजना बनानी चाहिए जो खड्ड और जनता के हलक तक पानी बरकरार रखे। ऐसी परियोजनाएं नहीं चाहिए जो खड्डों, जलप्रपातों या अन्य स्रोतों को सुखा दें। यहां धर्मशाला के वाटरफॉल से पहले नदी के पानी को जिस तरह एक सैन्य छावनी चूस रही है, उससे इसके अस्तित्व पर प्रश्न चश्मों हो गया है। ऐसे में अली खड्ड के पानी पर सर्वप्रथम उसी का हक है और इसी से जनता की प्यास बुझाने के लिए ऐसी अधोसंरचना व योजना बनानी होगी जो पहले से चल रही परियोजनाओं के लिए खतरा न बने, बल्कि बंटवारे के साथ न्याय की गारंटी का माहौल बनाना होगा।

राय एमएसपी की गारंटी नहीं

देश की राजधानी दिल्ली में 12 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई है। हरियाणा के करीब 15 जिलों में भी निषेधाज्ञा की स्थिति है। जाहिर है कि हालात सामान्य नहीं हैं। एक बार फिर किसान संगठनों ने लामबंद होकर 'दिल्ली कृष' का आह्वान किया है। भारतीय किसान यूनियन (राकेश टिकैत समूह) ने 16 फरवरी को 'भारत बंद' का आह्वान किया है। किसानों ने अपने आंदोलन के लिए संवेदनशील समय चुना है। देश में आम चुनाव की गतिविधियां आरंभ हो गई हैं। ऐसे मौके पर अपनी मांगों को लेकर भारत सरकार को झुकने पर बाध्य किया जाना चाहिए। राजधानी में एक माह तक लगातार धारा 144 लागू करने की स्थिति देशहित में नहीं है। दिल्ली के तीन बॉर्डर पर किलेबंदी भी की गई है। सड़क पर लोहे की कीलें गाड़ना, कंटीली तारें, लोहे और सीमेंट के विशालकाय अवरोधक, भारी कंटेनर और डंपर लावारिस रास्ते रोकने के दृश्य बीते किसान आंदोलन की याद ताजा कर रहे हैं। हरियाणा के कई जिलों में तो मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस की सेवाओं पर पाबंदियां चर्चा कर दी गई हैं। दिल्ली बॉर्डर और पंजाब-हरियाणा में सुरक्षा बलों अंजुमान के हजारों जवान तैनात किए गए हैं, मानो यह कोई भारत-पाकिस्तान सीमा हो और युद्ध के आसार हों। भारत सरकार और किसानों के बीच मतभेद और विवादस्पद समस्याएं सनातन रही हैं। केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल, कृषिमंत्री जगदीश प्रसाद और गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय की किसान नेताओं के संग बैठक और बातचीत बेनतीबा रही हैं, लेकिन बिजली कानून, 2020 को रद्द करने, लखीमपुर के किसानों को मुआवजा, पिछले आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवजनों को मुआवजा, किसानों पर दर्ज आपराधिक मामलों की वापसी आदि मुद्दों पर लगभग सहमति बन गई है, लेकिन बुनियादी गतिरोध न्यूनतम स्तर पर मूल्य (एमएसपी) के गारंटी कानून पर है। जब करीब दो साल पहले किसानों को आंदोलन समाप्त किया गया था, तब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इन मांगों को लेकर किसानों को आश्चर्य किया था। सवाल है कि सरकार एमएसपी पर अपनी नीति को स्पष्ट क्यों नहीं करती? यदि एमएसपी गारंटी कानून व्यावहारिक, संभव नहीं है, तो सरकार किसानों को अपना फैसला बतानी चाहिए? क्या आम चुनाव के मद्देनजर यह जोखिम नहीं उठाया जा सकता? वैसे भारत सरकार सिर्फ 23 फसलों पर ही एमएसपी की घोषणा करती है। उनमें भी गेहूं और धान की फसलों की खरीद ही एमएसपी पर होती है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा और भंडारण के लिए सरकार को इन फसलों की व्यापक खरीद करनी पड़ती है। सरकार जिन 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांटती है, उसके लिए भी थोक में बंदोबस्त करना अनिवार्य है। इसके बावजूद करीब 12-14 फीसदी किसानों को ही खरीद का लाभ मिल पाता है। शेष 85 फीसदी से अधिक किसान छोटे और सीमांत हैं। वे सरकार की खरीद के दायरे में बहुत कम आ पाते हैं। इसके अलावा, सरकार के लगातार प्रचार के बाद मोटे अनाज में अब बाजरे की खेती का क्षेत्र बढ़ा है, लिहाजा उसकी खरीद भी बढ़ी है। बाजरे का एमएसपी अच्छा-खासा घोषित किया जाता है। आंदोलित किसानों की सनातन और निरंतर मांग रही है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। इसके मायने होंगे कि सरकार ने काज पर उताना दाम दिलाने का वायदा किया है। खेती तो क्या, किसी भी उत्पाद का मूल्य सरकार तय नहीं कर सकती। यदि किसान संकट में हैं, तो अन्य समुदाय भी अपने आर्थिक और कारोबारी संकट लेकर सड़क पर उतर सकते हैं। सरकार किस-किस को गारंटी देती रहेगी? लिहाजा ऐसा कानून अव्यावहारिक है। अलबत पिछला आंदोलन वापस लेने के बाद भारत सरकार ने एक विशेष समिति का गठन किया था, जिसमें कुछ किसान प्रतिनिधियों को भी रखा गया था, लेकिन आज तक एमएसपी का मुद्दा अनसुलझा ही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन वर्गों को चुना है, उनमें गरीब, युवा, नारी के साथ किसान भी हैं।

प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत प्रतिबद्धता में से एक किसानों का सशक्तिकरण है। किसानों को सशक्त बनाना व उनकी आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री की ग्रामीण भारत की बेहतरी के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता है, जो भारत की अधिकांश आबादी को सशक्त बनाने और किसान समुदायों के उत्थान के लिए समर्पित हैं। समावेशी विकास पर एक मजबूत ध्यान देने के साथ, उनकी नीतियों और कार्यक्रमों को ग्रामीण और शहरी भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और नीम-लेपित यूरिया उर्वरक को बढ़ावा देने जैसी पहलों को लागू करके, मोदी ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों की भलाई सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को खाद्य टोकरी में विविधता लाने और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया है। बाजरा लचीला, पौष्टिक और जलवायु-स्मार्ट फसल होने के नाते, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने और किसानों की आजीविका में सुधार करने की क्षमता रखती हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजरा की खेती, खपत और व्यावसायिकरण को पुनर्जीवित करना है, जो अंततः किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभान्वित करता है। श्री अन्न वर्ष 2023 जैसी पहलों के माध्यम से, श्री अन्न की खेती के लिए किसानों को बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ती। धान के मुकाबले मोटे अनाज की खेती में पानी की खपत कम होती है। यूरिया और दूसरे रसायनों की जरूरत नहीं पड़ती है। इसकी खेती पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। पिछले कुछ सालों की तरह अगर दुनिया में यूं ही श्री अन्न की मांग बढ़ती है तो किसान कम लागत पर ज्यादा फायदा देने वाली फसल की पैदावार को और बढ़ा सकेंगे। भारत में उगाए जाने

वाले मोटे अनाजों में पल्लू मिले, ज्वार, फिंगर मिलेट और प्रोसो मिलेट, कोदो मिलेट, छोटा मिलेट, कंगनी मिलेट, ब्राउनटॉप मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, चौलाई और बकवटी जैसे गौण श्री अन्न शामिल हैं। भारत में मोटा अनाज खाने की परंपरा रही है। यह इनसान को सेहतमंद रखता है। भारत यही परंपरा अब दुनिया तक पहुंचाना चाहता है। पीएम मोदी ने मोटे अनाज को बढ़ावा देने की बात कही। हाल में मन की बात में भी उन्होंने इसका जिक्र किया है। सरकार की पहल के तहत ही संसद की कैंटीन में भी मोटे अनाज से बने व्यंजनों की शुरुआत हुई है। कैंटीन में देश के अलग-अलग इलाकों में फेमस मोटे अनाज से बने व्यंजन को खाने की सूची में शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, इस साल भारत में आयोजित होने वाले जी-20 कार्यक्रम में मोटे अनाज से बने पकवानों को विदेशी मेहमानों और वल्लू लीडर्स के सामने पेश किया है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। दुनिया भर में बाजरा को लोकप्रिय बनाने में भारत सबसे आगे रहा है। वेबामंडी की रिपोर्ट के अनुसार, मोटा अनाज मोटापा, दिल की बीमारियां, टाइप-2 डायबिटीज और कैंसर का खतरा घटाता है। यह बॉडी में ऐसे बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाता है जो आंतों की सेहत दुरुस्त रखते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसमें मौजूद फाइबर और ओषध तत्व।

यही वजह है कि मोटे अनाज को सुपर फूड भी कहते हैं। मोटे अनाज में फाइबर के साथ विटामिन-बी, फोलेट, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, आयरन और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शहरी-ग्रामीण विभाजन को पाटने, वित्तीय समावेशन को बढ़ाने और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया है।



किसान समुदायों की आबादी के बीच आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने किसान समुदायों की आबादी में उल्लेखनीय परिवर्तन लाया है। देश भर के किसानों का उत्थान किया है। उनके सम्पत्ति फसल के परिणामस्वरूप कई प्रभावशाली पहल हुई हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने औपचारिक ऋा तक पहुंच की सुविधा प्रदान की है, जिससे ग्रामीण उद्यमियों को अपने व्यवसाय को स्थापित करने और विस्तार करने में सक्षम बनाया गया है। इससे ग्रामीण समुदायों की जीवन स्थितियों में काफी सुधार हुआ है। पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम कृषि सिंचाई योजना और पीएम फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से किसान कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता स्पष्ट है। इन कार्यक्रमों ने क्रमशः वित्तीय सहायता, सिंचाई के बुनियादी ढांचे में वृद्धि और

फसल बीमा प्रदान किया है, जिससे किसानों की भलाई और समृद्धि सुनिश्चित हुई है। ग्रामीण भारत की बेहतरी के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने सकारात्मक बदलाव लाया है। अच्छी तरह से परिभाषित नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से मोदी ने किसान समुदाय के उत्थान और ग्रामीण और शहरी भारत की नींव को मजबूत करने के लिए अथक प्रयास किया है जिनका लाखों भारतीयों के जीवन पर निरन्तरकारी प्रभाव पड़ा है। मोदी ने कई किसान-केंद्रित नीतियों और कार्यक्रमों को लागू किया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य सिंचाई के बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से कृषि गतिविधियों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को फसल विफलताओं और प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए फसल बीमा प्रदान करती है।

जिससे उन्हें वित्तीय सुरक्षा मिलती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने टिकाऊ कृषि प्रथाओं और ग्रामीण विकास के महत्व पर जोर दिया है। नीम-लेपित यूरिया उर्वरक को बढ़ावा देने जैसी पहलों ने मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार किया है और कृषि के पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया है। जन-धन योजना ने ग्रामीण आबादी को बैंकिंग सेवाओं और किफायती बीमा तक पहुंच प्रदान करके वित्तीय समावेशन सुनिश्चित किया है। इसके बावजूद कहा जा रहा है कि किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। फिर से किसान आंदोलित हैं। उनकी मांगों पर सहानुभूति से विचार होना चाहिए।

डा. अमरीक ठाकुर
शिखाविद

कुत्ता, बिस्कुट और फिचफिच

का तर्क पूछा तो मैंने उससे कहा, ‘दोस्त! जिस दिन एक कविता लिखता हूं, उस दिन तुम सबको एक बिस्कुट के चार टुकड़े खिला देता हूं। जिस दिन दो कविताएं लिखता हूं, उस दिन दो बिस्कुट आठ टुकड़े कुत्तों को खिला देता हूं। ‘मतलब?’ ‘एक कुत्ता एक अफसर!’ तो उसने मुझे पुजारी की मुद्रा में आशीर्वाद देते कहा, ‘भगवान जब तुम दिन में दस दस कविताएं लिखेंगे ताकि हमें चालीस चालीस बिस्कुट के टुकड़े खाने को मिलें।’

कुत्ते से लिखने का आशीर्वाद प्राप्त कर कल मैंने पांच कविताएं लिखीं। पर मैंने तब कुत्ते को बिस्कुट खिलाने से अपना हाथ पीछे खींच लिया। हालांकि मैंने ईमानदारी से जेब में पांच बिस्कुट डाले हुए थे। सामने कुत्ता आया तो उसने मुझसे एक बिस्कुट के चार टुकड़े कर खिलाने के पीछे

‘क्यों?’ ‘उस हिसाब से हम कुत्तों को बिस्कुट के टुकड़े को मिलेंगे। क्या आज तुमने कुछ लिखा नहीं?’ ‘कवि मर सकता है, पर लिखना नहीं छोड़ सकता। लिखना तब तक जारी रखूंगा जब तक मुझे पुरस्कार नहीं मिल जाता।’ ‘तो आज अफसरों का हिस्सा! पर पुरस्कार केवल लिखने के प्रियों को पुरस्कार मिला करते हैं। नेताओं के चमचों को पुरस्कार मिला करते हैं। जिनको प्रियों को पुरस्कार मिला करते हैं। जिनको प्रियों को पुरस्कार देने से राजनीतिज्ञों को उनका वोट बैंक बढ़ने की उम्मीद हो उन्हें पुरस्कार मिला करते हैं। अब आज लिखी कविताओं के हिसाब से हमारे

बिस्कुट लाओ। ‘डियर! बुरा मत मानना! जबसे कुत्ते द्वारा उनके हाथों से बिस्कुट न खाने पर राजनीति हो रही है, तबसे तुम्हें बिस्कुट खिलाने से बहुत डर रहा हूं। बैचारों ने इतने सालों से सत्ता से बाहर रहते हुए भी कुत्ते को बिस्कुट खिलाने का साहस किया। धन्य है वे! जिस देश में कुत्ते भी बिस्कुट खाने से मुंह फेरने लगे तो समझ लीजिएगा, उस देश में आदमियों से उच्च जीवन स्तर कुत्तों का हो गया है। प्रति व्यक्ति स्वाद स्तर से ऊंचा कुत्तों का स्वाद स्तर हो गया है। ऐसे में, कहीं तुमने भी जो मेरे हाथों से आज बिस्कुट नहीं खाया और उसका वीडियो पुरस्कार देने से राजनीतिज्ञों को उनका वोट बैंक मिलने के विरुद्ध मोर्चा खोलो को एक और मुद्दा खिल जाएगा कि जिसके हाथों से कुत्ते ने बिस्कुट

खाने से मुंह फेर लिया, उस लेखक के हाथों से लिखी कविताओं को पाठक क्यों खाएगा। अतः जिस तरह उनको अब राजनीति छोड़ देनी चाहिए, उसी तरह मुझे भी लिखना छोड़ देना चाहिए। साहित्य की भलाई इसी में है।’ ‘देखी कुत्ते की फकादारी! तुम्हारी तरह नहीं कि जहां से खाने को मिला, उधर को पाला बदल लिया। पर पगले! मैं राजनीतिक कुत्ता नहीं हूं, कह उसने मेरी बिस्कुट वाली जेब को घाटन शुरू किया। ‘कुत्ते भी किस्म किस्म के होते हैं?’ ‘हां! राजनीतिक कुत्ते, धार्मिक कुत्ते, सांस्कृतिक कुत्ते, प्रचारी कुत्ते, व्यवहारी कुत्ते, सदाचारी कुत्ते, दुराचारी कुत्ते, सवारी कुत्ते, बीमारी कुत्ते, नहामारी कुत्ते, लुच्चे कुत्ते, सुच्चे कुत्ते, मांसाहारी कुत्ते, शाकाहारी कुत्ते, फाकाहारी कुत्ते। आम आदमियों की तरह आम श्रेणी के कुत्ते आदि आदि। ‘तो तुम कैसे कुत्ते हो?’ ‘तुम्हारी तरह आम श्रेणी का कुत्ता। उसने कहा और अपनी जीभ मेरी जेब में घुसा दी।

अग्रहोगौतम

